



भारत का राजपत्र

The Gazette of India

साप्ताहिक/WEEKLY
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 31] नई दिल्ली, शनिवार, अगस्त 4—अगस्त 10, 2007 (श्रावण 13, 1929)
No. 31] NEW DELHI, SATURDAY, AUGUST 4—AUGUST 10, 2007 (SRAVANA 13, 1929)

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।
(Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation)

भाग I—खण्ड-1—(रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) भारत सरकार के मंत्रालयों और उच्चतम न्यायालय द्वारा जारी की गई विधितर नियमों, विनियमों, आदेशों तथा संकल्पों से सम्बन्धित अधिसूचनाएं	873
भाग I—खण्ड-2—(रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) भारत सरकार के मंत्रालयों और उच्चतम न्यायालय द्वारा जारी की गई सरकारी अधिकारियों की नियुक्तियों, पदोन्ततियों, छुट्टियों आदि के सम्बन्ध में अधिसूचनाएं	725
भाग I—खण्ड-3—रक्षा मंत्रालय द्वारा जारी किए गए संकल्पों और असांविधिक आदेशों के सम्बन्ध में अधिसूचनाएं	3
भाग I—खण्ड-4—रक्षा मंत्रालय द्वारा जारी की गई सरकारी अधिकारियों की नियुक्तियों, पदोन्ततियों, छुट्टियों आदि के सम्बन्ध में अधिसूचनाएं	1233
भाग II—खण्ड-1—अधिनियम, अध्यादेश और विनियम	*
भाग II—खण्ड-1क—अधिनियमों, अध्यादेशों और विनियमों का हिन्दी भाषा में प्राधिकृत पाठ	*
भाग II—खण्ड-2—विधेयक तथा विधेयकों पर प्रवर समितियों के बिल तथा रिपोर्ट	*
भाग II—खण्ड-3—उप खण्ड (i)—भारत सरकार के मंत्रालयों (रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) और केन्द्रीय प्राधिकरणों (संघ शासित क्षेत्रों के प्रशासनों को छोड़कर) द्वारा जारी किए गए सामान्य सांविधिक नियम (जिनमें सामान्य स्वरूप के आदेश और उपविधियां आदि भी शामिल हैं	*
भाग II—खण्ड-3—उप खण्ड (ii)—भारत सरकार के मंत्रालयों (रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) और केन्द्रीय प्राधिकरणों (संघ शासित क्षेत्रों के प्रशासनों को छोड़कर) द्वारा जारी किए गए सामान्य सांविधिक आदेश और अधिसूचनाएं	*

भाग II—खण्ड-3—उप खण्ड (iii)—भारत सरकार के मंत्रालयों (जिसमें रक्षा मंत्रालय भी शामिल है) और केन्द्रीय प्राधिकरणों (संघ शासित क्षेत्रों के प्रशासनों को छोड़कर) द्वारा जारी किए गए सामान्य सांविधिक नियमों और सांविधिक आदेशों (जिनमें सामान्य स्वरूप की उपविधियां भी शामिल हैं) के हिन्दी प्राधिकृत पाठ (ऐसे पाठों को छोड़कर जो भारत के राजपत्र के खण्ड 3 या खण्ड 4 में प्रकाशित होते हैं).....	*
भाग II—खण्ड-4—रक्षा मंत्रालय द्वारा जारी किए गए सांविधिक नियम और आदेश	*
भाग III—खण्ड-1—उच्च न्यायालयों, नियंत्रक और महालेखापरीक्षक, संघ लोक सेवा आयोग, रेल विभाग और भारत सरकार से सम्बद्ध और अधीनस्थ कार्यालयों द्वारा जारी की गई अधिसूचनाएं	3443
भाग III—खण्ड-2—पेटेंट कार्यालय द्वारा जारी की गई पेटेंटों और डिजाइनों से सम्बन्धित अधिसूचनाएं और नोटिस	539
भाग III—खण्ड-3—मुख्य आयुक्तों के प्राधिकार के अधीन अथवा द्वारा जारी की गई अधिसूचनाएं	*
भाग III—खण्ड-4—विधिक अधिसूचनाएं जिनमें सांविधिक नियमों द्वारा जारी की गई अधिसूचनाएं, आदेश, विज्ञापन और नोटिस शामिल हैं	10615
भाग IV—गैर-सरकारी व्यक्तियों और गैर-सरकारी निकायों द्वारा जारी किए गए विज्ञापन और नोटिस	559
भाग V—अंग्रेजी और हिन्दी दोनों में जन्म और मृत्यु के आंकड़ों को दर्शाने वाला सम्पूरक	*

CONTENTS

PART I—SECTION 1—Notifications relating to Non-Statutory Rules, Regulations, Orders and Resolutions issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Supreme Court	873	than the Administration of Union Territories).....*
PART I—SECTION 2—Notifications regarding Appointments, Promotions, Leave etc. of Government Officers issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Supreme Court	725	PART II—SECTION 3—SUB-SECTION (iii)—Authoritative texts in Hindi (other than such texts, published in Section 3 or Section 4 of the Gazette of India) of General Statutory Rules & Statutory Orders (including Bye-laws of a general character) issued by the Ministries of the Government of India (including the Ministry of Defence) and by Central Authorities (other than Administration of Union Territories)
PART I—SECTION 3—Notifications relating to Resolutions and Non-Statutory Orders issued by the Ministry of Defence.....	3	PART II—SECTION 4—Statutory Rules and Orders issued by the Ministry of Defence
PART I—SECTION 4—Notifications regarding Appointments, Promotions, Leave etc. of Government Officers issued by the Ministry of Defence.....	1233	PART III—SECTION 1—Notifications issued by the High Courts, the Comptroller and Auditor General, Union Public Service Commission, the Indian Government Railways and by Attached and Subordinate Offices of the Government of India
PART II—SECTION 1—Acts, Ordinances and Regulations.....	*	PART III—SECTION 2—Notifications and Notices issued by the Patent Office, relating to Patents and Designs.....
PART II—SECTION 1A—Authoritative texts in Hindi languages of Acts, Ordinances and Regulations	*	PART III—SECTION 3—Notifications issued by or under the authority of Chief Commissioners
PART II—SECTION 2—Bills and Reports of the Select Committee on Bills.....	*	PART III—SECTION 4—Miscellaneous Notifications including Notifications, Orders, Advertisements and Notices issued by Statutory Bodies.....
PART II—SECTION 3—SUB-SECTION (i)—General Statutory Rules including Orders, Bye-laws, etc. of general character issued by the Ministry of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Central Authorities (other than the Administration of Union Territories).....	*	PART IV—Advertisements and Notices issued by Private Individuals and Private Bodies
PART II—SECTION 3—SUB-SECTION (ii)—Statutory Orders and Notifications issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Central Authorities (other	*	PART V—Supplement showing Statistics of Births and Deaths etc. both in English and Hindi.....*

*Folios not received.

भाग I—खण्ड 1

[PART I—SECTION 1]

[(रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) भारत सरकार के मंत्रालयों और उच्चतम न्यायालय द्वारा जारी की गई विवितर नियमों, विनियमों तथा आदेशों और संकल्पों से संबंधित अधिसूचनाएं]

[Notifications relating to Non-Statutory Rules, Regulations, Orders and Resolutions issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Supreme Court]

कार्यिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय
(प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग)

नई दिल्ली, दिनांक 17 जुलाई 2007

संकल्प

सं. के-11022/26/2007-प्र.सु.—राष्ट्रपति, दूसरे प्रशासनिक सुधार आयोग द्वारा सरकार को अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिए इसकी अवधि सात माह के लिए दिनांक 31.3.2008 तक बढ़ाते हैं।

शशि कांत शर्मा
अपर सचिव

मानव संसाधन विकास मंत्रालय
(उच्चतर शिक्षा विभाग)

नई दिल्ली, दिनांक 16 जुलाई 2007

सं. एफ. 20-28/2006-यू. 3-ए—जबकि विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम, 1956 की धारा 3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्र सरकार को विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की सलाह पर उपर्युक्त अधिनियम के प्रयोजनार्थ उच्चतर शिक्षण की किसी संस्था को सम-विश्वविद्यालय घोषित करने का अधिकार प्राप्त है;

2. और जबकि भारती विद्यापीठ, पुणे जिसमें शिक्षा के विभिन्न क्षेत्रों के 12 शिक्षण संस्थान शामिल हैं, को इस मंत्रालय की दिनांक 26 अप्रैल, 1996 की अधिसूचना सं. एफ. 9-15/95-यू. 3 के माध्यम से विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम, 1956 की धारा 3 के तहत सम विश्वविद्यालय घोषित किया था।

3. और जबकि विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की सलाह पर इस मंत्रालय की दिनांक 28.7.2000 की अधिसूचना सं. एफ. 9-15/95-यू. 3, दिनांक 19.8.2004 की अधिसूचना सं. एफ. 9-7/2004-यू. 3, दिनांक 25.2.2005 की अधिसूचना सं. 9-16/2004-यू. 3 और दिनांक 14.2.2007 तथा 6.6.2007 की समसंख्यक अधिसूचनाओं के माध्यम से उक्त अधिनियम के प्रयोजनार्थ भारती विद्यापीठ, सम विश्वविद्यालय, की परिधि के अन्तर्गत इसके घटक एककों के रूप में 17 अन्य शिक्षण संस्थाओं को सम्मिलित किया गया।

4. अब इसलिए विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम, 1956 की धारा 3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्र सरकार, विश्वविद्यालय

अनुदान आयोग की सलाह पर एतद्वारा यह घोषित करती है कि नवी मुम्बई में 'भारती विद्यापीठ मेडिकल कालेज और अस्पताल' के नाम स्थापित किए जाने वाली प्रस्तावित संस्था उपर्युक्त अधिनियम के प्रयोजनार्थ "भारती विद्यापीठ" सम विश्वविद्यालय के अधिकार क्षेत्र के अन्तर्गत एक संघटक शिक्षण इकाई होगी जो भारतीय चिकित्सा परिषद की सिफारिश पर भारतीय चिकित्सा परिषद अधिनियम, 1956 के अन्तर्गत स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार के पूर्व अनुयोदन से औपचारिक रूप से स्थापित तारीख से प्रभावी होगा।

5. यह घोषणा इस अधिसूचना के पृष्ठांकन की क्र. सं. 5 में डिल्लिखित शर्तों के आधार पर निर्भर करेगी।

6. मानव संसाधन विकास मंत्रालय या विश्वविद्यालय अनुदान आयोग भारती विद्यापीठ, सम विश्वविद्यालय या इसकी किसी संघटक संस्था को कोई योजनागत और योजनेतर अनुदान प्रदान नहीं करेगा।

सुनील कुमार
संयुक्त सचिव

दिनांक 17 जुलाई 2007

सं. एफ. 9-33/2002-यू. 3—जबकि केन्द्र सरकार को विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम, 1956 की धारा 3 के तहत विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की सलाह पर उच्चतर शिक्षण की किसी संस्था को सम-विश्वविद्यालय घोषित करने का अधिकार प्राप्त है;

2. और जबकि केन्द्र सरकार को विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम, 1956 की धारा 3 के तहत शिक्षा और अनुसंधान, भुवनेश्वर को सम विश्वविद्यालय घोषित करने हेतु एक प्रस्ताव प्राप्त हुआ था।

3. और जबकि विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने उपरोक्त प्रस्ताव की जांच की है और दिनांक 18 जनवरी, 2007 के अपने पत्र संख्या एफ 6-65/2004-(सीपीपी-I) सिफारिश की है कि शिक्षा और अनुसंधान, भुवनेश्वर, जिसकी छ. घटक संस्थाएं हैं, के नाम से विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम, 1956 की धारा 3 के तहत सम विश्वविद्यालय घोषित किया जाए; बशर्ते कि दो वर्ष पश्चात् इसकी समीक्षा की जाएगी।

4. अतः विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम, 1956 की धारा 3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्र सरकार, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की सलाह पर एतद्वारा शिक्षा और अनुसंधान, भुवनेश्वर, डड़ीसा, जिसमें निम्नलिखित पांच संस्थाएं शामिल हैं को उपर्युक्त अधिनियम के प्रयोजनार्थ उस तिथि से जब से निम्नलिखित संस्थाओं ने अपनी सम्बंधित विश्वविद्यालयों नामतः बीजू पट्टनायक बौद्धिगिकी विश्वविद्यालय, राउरकेला तथा उत्कल विश्वविद्यालय, भुवनेश्वर से सम्बद्धन समाप्त किया है, विश्वविद्यालय के रूप में घोषित करती है, बशर्ते कि विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की विशेषज्ञ समिति द्वारा दो वर्ष के पश्चात् इसकी समीक्षा की जाए।

- (i) तकनीकी शिक्षा तथा अनुसंधान संस्थान
- (ii) व्यवसाय तथा संगणक अध्ययन संस्थान
- (iii) होटल प्रबंधन स्कूल
- (iv) दंत विकित्सा संस्थान
- (v) एस यू एम नर्सिंग कालेज

(5) उपरोक्त पैरा 4 में की गई घोषणा इस अधिसूचना के पृष्ठांकन की क्रम संख्या 7 में उल्लिखित शर्तों के भी अधीन है।

(6) भारत सरकार अथवा विश्वविद्यालय अनुदान आयोग शिक्षा और अनुसंधान अथवा इसकी संघटक शिक्षण इकाईयों को कोई योजनागत अथवा योजनेतर अनुदान नहीं देंगे।

सुनिल कुमार
संयुक्त सचिव

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय
(दूरसंचार विभाग)

नई दिल्ली, दिनांक 29 मार्च 2007

संकल्प

सं. 1-03/2006-एसईए-1--सरकार ने सदस्य (वित्त), दूरसंचार आयोग के समग्र कार्यभार के अधीन दूरसंचार विभाग का भाग रहे संचार लेखा नियंत्रक के कार्यालयों में अधिकारियों के पदनाम को निम्नानुसार परिवर्तित करने का निर्णय लिया है :

एचएजी-II	- प्रथान संचार लेखा नियंत्रक
जेएजी (एनएफएसजी)	- अपर संचार लेखा नियंत्रक

अन्य अधिकारियों के पदनाम निम्नानुसार अपरिवर्तित रहेंगे :

एसएजी	- संचार लेखा नियंत्रक
जेएजी	- संयुक्त संचार लेखा नियंत्रक
एसटीएस	- उप संचार लेखा नियंत्रक
जेटीएस	- सहायक संचार लेखा नियंत्रक
एओ	- संचार लेखा अधिकारी
जेएओ	- कनिष्ठ संचार लेखा अधिकारी

आदेश

आदेश दिया जाता है कि संकल्प की एक प्रति सभी संबंधितों को भेजी जाए।

यह भी आदेश दिया जाता है कि उक्त संकल्प को बतौर सामान्य सूचना राजपत्र में प्रकाशित किया जाए।

माधवी दास
निदेशक (एसईए)

MINISTRY OF PERSONNEL, PUBLIC GRIEVANCES AND
PENSIONS
(DEPARTMENT OF ADMINISTRATIVE REFORMS &
PUBLIC GRIEVANCES)

New Delhi, the 17th July 2007

RESOLUTION

No. K-11022/26/2007-AR—The President is pleased to extend the term of the second Administrative Reforms Commission (ARC) by seven months upto 31.3.2008 for submission of its Reports to the Government.

SHASHI KANT SHARMA
Additional Secy.

MINISTRY OF HUMAN RESOURCE DEVELOPMENT
(DEPARTMENT OF HIGHER EDUCATION)

New Delhi-1, the 16th July 2007

No. F. 20-28/2006-U. 3(A)—Whereas the Central Government is empowered under Section 3 of the University Grants Commission (UGC) Act, 1956 to declare, on the advice of the UGC, an institution of higher learning as a deemed-to-be-university for the purpose of said Act.

2. And whereas, Bharati Vidyapeeth, Pune, comprising 12 teaching institutions in various fields of education, was declared a deemed-to-be-university under Section 3 of the UGC Act, 1956 vide this Ministry's notification No. F. 9-15/95-U. 3 dated the 26th April, 1996.

3. And whereas, on the advice of the UGC, 17 more teaching institutions were included under the ambit of Bharati Vidyapeeth, Deemed-to-be-University, Pune, as its constituent units, for the purposes of the aforesaid Act, vide this Ministry's notifications No. F. 9-15/95-U. 3 dated 28.07.2000, No. F. 9-7/2004-U. 3 dated 19.08.2004, No. F. 9-16/2004-U. 3 dated 25.02.2005, and of even number dated 14.02.2007 & 06.06.2007.

4. Now therefore, in exercise of the powers conferred by Section 3 of the University Grants Commission (UGC) Act, 1956, the Central Government, on the advice of the UGC, do hereby declare that the institution proposed to be established in the name of 'Bharati Vidyapeeth's Medical College and Hospital' at Navi Mumbai, will be a constituent teaching unit under the ambit of 'Bharati Vidyapeeth', 'Deemed-to-be-University', Pune for the purpose of the aforesaid Act, with effect from the date on which it is formally established with the prior approval of the Ministry of Health and Family Welfare, Government of India, under the Indian Medical Council Act, 1956, on the recommendation of the Medical Council of India (MCI).

5. The declaration is subject to the conditions mentioned at Sl. No. 5 of the endorsement of this notification.

6. The Ministry of Human Resource Development or the University Grants Commission will not provide any Plan

and Non-Plan grants either to the Bharati Vidyapeeth, Deemed-to-be-University or any of its constituent institutions.

SUNIL KUMAR
Joint Secy.

The 17th July 2007

No. F. 9-33/2002-U. 3—Whereas the Central Government is empowered under Section 3 of the University Grants Commission (UGC) Act, 1956 to declare, on the advice of the UGC, an institution of higher learning as a deemed-to-be-university.

2. And whereas, a proposal was received for grant of status of deemed-to-be-university to Siksha 'O' Anusandhan, Bhubaneswar under Section 3 of the UGC Act, 1956.

3. And whereas, the University Grants Commission have examined the said proposal and vide their communication No. F. 6-65/2004(CPP-I) dated the 18th January, 2007 have recommended conferment of status of 'deemed-to-be-university' to Siksha 'O' Anusandhan, Bhubaneswar, comprising six constituent institutions, under Section 3 of the UGC Act, 1956, subject to a review after two years.

4. Therefore, in exercise of the powers conferred by Section 3 of the University Grants Commission Act, 1956, the Central Government, on the advice of the University Grants Commission (UGC), hereby declare that Siksha 'O' Anusandhan, Bhubaneswar, Orissa, comprising the following five institutions, shall be deemed to be a university for the purposes of the aforesaid Act, with effect from the date the following institutions are disaffiliated from their respective affiliating universities, namely, Biju Patnaik University of Technology, Rourkela and Utkal University, Bhubaneswar, subject to a review after two years by an Expert Committee of the UGC.

- (i) Institute of Technical Education & Research
- (ii) Institute of Business & Computer Studies
- (iii) School of Hotel Management
- (iv) Institute of Dental Sciences
- (v) SUM Nursing College.

5. The declaration made in para 4 above is also subject to further conditions mentioned at Sr. No. 7 of the endorsement to this Notification.

6. Neither the Government of India nor the University Grants Commission shall provide any Plan and Non-Plan grant-in-aid to Siksha 'O' Anusandhan or any of its constituent units.

SUNIL KUMAR
Joint Secy.

**MINISTRY OF COMMUNICATIONS & IT
(DEPARTMENT OF TELECOMMUNICATIONS)**

New Delhi, the 29th March 2007

RESOLUTION

No. 1-03/2006-SEA-I—The Government has decided to change the designation of officers in the offices of the Controller of Communication Accounts, which are a part of Department of Telecommunications under the overall charge of Member (Finance), Telecom. Commission as follows :

HAG-II—Principal Controller of Communication Accounts
JAG (NFSG)—Additional Controller of Communication Accounts

The designation of the other Officers would remain unchanged as follows :

SAG—Controller of Communication Accounts
JAG—Joint Controller of Communication Accounts

STS—Deputy Controller of Communication Accounts
JTS—Assistant Controller of Communication Accounts
AO—Communication Accounts Officer
JAO—Junior Communication Accounts Officer

ORDER

ORDERED that a copy of the resolution be communicated to all concerned.

ORDERED also that the resolution be published in the Gazette of India general information.

MADHAVI DAS
Director (SEA)